(d) Details of cloth production in Powerloom Sector:—

(in million sq mts)

Year	Production
1989-90	11404
1990-91	12746
1991-92	12742

Export performance of Powerloom Sector:—

(Rs. in crore)

Year	Value
1989-90	283.86
1990-91	323.33
1991-92	547.36

Import of Angora Wool

1851. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government has liberalised the import of Angora Wool; and

(b) if so, what effects doe this have on the domestic production of Angora Wool?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Import of Angora Wool is not in the negative list of the Import Policy announced for 1992—97 and as such Import can be made by any person.

(b) There is no report of any substantial Import of Angora Wool which may have any effect on its domestic production.

गुजरात में हथकरघा बुनकरों के सामने पेश आ रही समस्यायें

1852. **श्री राजूभाई ए० परमार :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में हथकरघा बुनकरों के सामने पेश आ रही समस्याओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) देश में हथ करघा बुनकरों, जिसमें गुजरात के बुनकर भी शामिल हैं, की मुख्य समस्या सूत के बढ़ते हुए मूल्य हैं। सरकार सूत के मूल्य की निरंतर समीक्षा कर रही है और इस संबंध में कई उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं । राज्य क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों को निदेश दिये गये हैं कि वे संगीन काऊंट के सूत के उत्पादन में वृद्धि करें और मूल्यों में रोक-थाम करें । राष्ट्रीय वस्त्र निगम को निदेश दिये गये हैं कि वे अपनी उत्पादन योजना में इस प्रकार व्यवस्था करें जिससे 40 एस० और उससे कम कॉऊंट के हैंक यान के उत्पादन में वृद्धि हो क्योंकि इस प्रकार के सूत के मूल्य में हुई वृद्धि से हथकरघा बुनकर अधिक प्रभावित हुए हैं । राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि सहकारी/राज्य क्षेत्र की मिलों द्वारा उत्पादित सूत की देखरेख करें और हैंक सूत की सप्लाई, इसके मूल्यों और वितरण के संबंध में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा करें । मुख्य मंत्रियों को यह भी सलाह दी गई है कि सूत की जमाखोरी को रोकने के लिए जिला अधिकारियों को निदेश दें कि वे अपने-अपने जिले में सूत वितरकों के स्टाक और सूत के विक्रय मूल्यों की निरंतर जांच करें । राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से भी कहा गया है कि हथकरघा बुनकरों की आपूर्ति के लिए सूत के उत्पादन म वृद्धि करें। चालू वर्ष के दौरान सरकार हथकरघा बुनकरों को मिलगेट मूल्यों पर राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा सूत

सप्लाई करने की एक योजना भी कार्यान्वित कर रही है ।

राज्यों को जनता कपड़ा आबंटित करने का आधार

1853. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कपड़े का राज्यवार आबंटन किसी राज्य में चालित हथकरघों की संख्या और उनकी पिछली उत्पादन क्षमता के आधार पर तय किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में वार्षिक उत्पादन क्या रहा है ;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष जनता कपड़े की कितनी मात्रा आबंटित की गई और वर्ष 1992–93 के लिए इस संबंध में प्रस्तावित लक्ष्य क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को जनता कपड़ा आसानी से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान क्रमश: 119 14 मिलियन वर्ग मीटर और 100 मिलियन वर्ग मीटर जनता कपड़े का उत्पादन हुआ ।

(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को आबंटन किये जाने के लिए जनता कपड़े का लक्ष्य इस प्रकार है :—

(मिलियन वर्ग मीटर में)

वर्ष	उत्पादन का लक्ष्य
1990–91	132.00
1991–92	100.00
19 92–93	100.00

(घ) लक्षित समूह में जनता कपड़े की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा निदेश दिये गये हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को जनता कपड़े का वितरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें । जनता कपड़े के वितरण के लिए जारी मार्गदर्शिका में यह प्रावधान है कम से कम 75% कपड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के लक्षित समूह को बेचा जाये । ग्रामीण-पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अभि-करणों का पता लगाया जाये जिनके 3 वितरण विक्रय केन्द्र हों ।

Announcement of Textiles Policy

1854. SHRI SOM PAL:
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:

Will the Minister of TEXTILES be-pleased to state:

(a) whether Government propose to announce the new Textile Policy; and

(b) if so, by when announcement in this regard is likely to be made?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) Government do not intend to announce a new textile Policy for the time being.

Textile Mills under Public Sector in Andhra Pradesh

1855. SHRI TINDIVANAM G. VENKATARAMAN:
DR. NARREDDY THULASI REDDY;

Will the Minister of TEXTILES be ple ased to state:

(a) what is the number of textile mills under public sector are there in Tamil Nadu and Andhra Pradesh;

(b) what is the number out of them which are working at profit or loss;